[2023] 12 एस. सी. आर 753:2023 आई. एन. एस. सी. 856

मुकदमों का विवरण

सीता सोरेन बनाम।

भारत का संघ

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 451) सितंबर 20, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई,

ए. एस. बोपन्ना, एम. एम. सुंदरेश, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे।]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःमुद्दा इस बात से संबंधित है कि क्या कोई सांसद या विधायक सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या मतदान करने के लिए रिश्वत लेने के लिए आपराधिक अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है; और पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले की शुद्धता के बारे में।

भारत का संविधान–अनुच्छेद 194 (2)–विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि– पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या मतदान करने के लिए रिश्वत लेने के लिए किसी सांसद या विधायक को आपराधिक अभियोजन से प्रतिरक्षा के संबंध में मुद्दा–सच्चाईः

आयोजित किया गयाःपी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण में राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के संरक्षण के लिए गंभीर निहितार्थ हैं–इसके मद्देनजर, पी. वी. नरसिम्हा राव में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता पर सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना है–बड़ी पीठ को संदर्भ।

न्यायिक अनुशासन–किसी निर्णय की शुद्धता–पुनर्विचारः

आयोजित किया गयाःन्यायिक अनुशासन की यह स्थिर स्थिति है कि केवल समान संख्या वाली पीठ ही समान संख्या वाली पिछली पीठ द्वारा लिए गए विचार की शुद्धता पर संदेह करते हुए राय व्यक्त कर सकती है–यदि ऐसा संदेह व्यक्त किया जाता है, तो मामले को उस पीठ के समक्ष रखा जा सकता है जिसमें उस पीठ से बड़ी गणपूर्ति हो जो निर्णय को चुनौती देने वाली थी।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) (1998) 4 एस. सी. सी. 626:[1998] 2 एस. सी. आर. 870; राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) बनाम पी. वी. नरसिम्हा राव (2001) 9 एस. सी. सी. 249; सेंटर फॉर पी. आई. एल. एंड ए. एन. आर. वी.भारत संघ (2000) 9 एस. सी. सी. 393; रूपा अशोक हुर्रा बनाम.

अशोक हुर्रा और अन्र। (2002) 4 एससीसी 388:[2002] 2 एससीआर 1006; पशुपति

नाथ सुकुल बनाम नेम चंद्र जैन और अन्य। (1984) 2 एससीसी 404:[1984] 1 एस. सी. आर. 939; मधुर जेटली बनाम भारत संघ और अन्य। (1997) 11 एस. सी. सी. 111; कुलदिप नायर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2006) 7 एससीसी 1:[2006] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 1; जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39:[2018] 11 एससीआर 765; कल्पना मेहता बनाम भारत संघ (2018) 7 एससीसी 1:[2018] 4 एस. सी. आर. 1–संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:आपराधिक अपील सं. 451

2019.

2013 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. संख्या 128 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.02.2014 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक सिंह, कौशिक लाइक, अक्षय कौशिक, शशांक तिवारी, एम. वी. मुकुंद, राहुल आर्य, प्रताप शंकर, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री तन्वी आनंद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

आर. वेंकटरमानी, ए. जी. आई., तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., परमजीत सिंह पटवालिया, सीनियर एड., (ए. सी.), गोपाल शंकरनारायण, सीनियर एड., सुश्री हर्षिका वर्मा, दीपांशु कृष्ण, गौरवजीत सिंह पटवालिया, मनन डागा, सुश्री समराधी श्रीवास्तव, गौरव अग्रवाल, कानू अग्रवाल, सुश्री चिनमयी चंद्र, के परमेश्वर, उदय खन्ना, अक्षय अमृतांशु, अनमोल चंदन, अंकुर तलवार, आनंद वेंकटरमानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी वेंकटरमानी, विनायक मेहरोत्रा, सुश्री मानसी सूद, चितवन सिंह। फैज़, सुश्री सविता कुमारी, अमित पवन, अश्विनी कुमार उपाध्याय, अश्विनी कुमार दुबे, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, विशाल सिन्हा, सुश्री शिवानी विज, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय
का निर्णय/आदेश

ओ आर डी ई आर

1. आपराधिक अपील 2013 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 128 में झारखंड उच्च न्यायालय के 17 फरवरी 2014 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है।

2. 30 मार्च 2012 को झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के दो सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था।अपीलार्थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित विधान सभा का सदस्य था।एप पेलेंट के खिलाफ आरोप है कि उसने एक निर्दलीय उम्मीदवार से उसके पक्ष में वोट डालने के लिए रिश्वत ली थी।हालाँकि, जैसा कि राज्यसभा सीट के लिए खुले मतदान से पता चला है, उन्होंने कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में अपना वोट नहीं डाला और इसके बजाय अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डाला।विचाराधीन चुनाव के दौर को रद्द कर दिया गया और एक नया चुनाव आयोजित किया गया जिसमें अपीलार्थी ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया।

3. अपीलार्थी ने आरोप पत्र और उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के प्रावधानों पर भरोसा किया।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले द्वारा आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने से इनकार कर दिया कि अपीलार्थी ने कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में अपना वोट नहीं दिया था और इस प्रकार, वह अनुच्छेद 194 (2) के तहत संरक्षण का हकदार नहीं है।4. उच्च न्यायालय के फैसले ने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।5. 23 सितंबर 2014 को, जब इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष कार्यवाही रखी गई, तो न्यायालय का विचार था कि चूंकि विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा "पर्याप्त और सामान्य सार्वजनिक महत्व का" है, इसलिए इसे इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

6. 7 मार्च 2019 को, जब इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपील की सुनवाई की, तो उसने नोट किया कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप की गंभीरता यह है कि उसने झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के लिए राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए रिश्वत स्वीकार की थी।सटीक प्रश्न, जैसा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. आई./आई.

एसपीई)1. पीठ के दो न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद ने यह विचार व्यक्त किया कि अनुच्छेद 105 (2) के तहत और तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत दी गई प्रतिरक्षा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने या मतदान करने के लिए रिश्वतखोरी का आरोप लगाया जाता है।हालाँकि, बहुमत का विचार इसके विपरीत था।

7. वर्तमान अपील की सुनवाई कर रही तीन–न्यायाधीशों की पीठ का विचार था कि "जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उसके व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उठाए गए संदेह और मुद्दा सार्वजनिक महत्व का विषय होने के कारण", इसे एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है, जिसे उचित माना जा सकता है।तदनुसार, मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, पांच न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष रखा गया है।8. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना उचित होगा कि पी. वी. नरसिम्हा राव में संवैधानिक स्थिति की शुद्धता को चुनौती देने के पूर्व प्रयासों का फल नहीं मिला है।पी. वी. नरसिम्हा राव में निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिकाएं (समीक्षा याचिका संख्या 2210–27/1998) दायर की गईं। 18 जुलाई 2002 को समीक्षा याचिकाओं को राज्य (सी. बी. आई./आई. सी. बी. आई.) के रूप में रिपोर्ट की गई समीक्षा याचिकाओं के अंतिम चरण में 177 दिनों की देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

एसपीई) बनाम पी. वी. नरसिम्हा राव 2.

9. उपरोक्त के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 32 (रिट याचिका (सिविल) डायरी संख्या 7490/99) के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पी. वी. नरसिम्हा राव में स्थिति की शुद्धता पर घोषणा करने की मांग की गई थी।केंद्र में 1 मई 2000 के एक आदेश द्वारा

पी. आई. एल. और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ 3 के लिए, इसके तीन न्यायाधीशों की एक पीठ

अदालत ने याचिका की स्थिरता के संबंध में एक प्रस्तुति पर ध्यान देते हुए याचिका को पांच न्यायाधीशों की एक पीठ को भेज दिया।आखिरकार, 18 जुलाई 2002 के एक आदेश द्वारा, रूपा अशोक हुर्रा बनाम मामले के फैसले को देखते हुए याचिका को विचारणीय होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

अशोक हुर्रा और अन्र 4.

1 (1998) 4 एससीसी 626 2 (2001) 9 एससीसी 249 3 (2000) 9 एससीसी 393 4 (2002) 4 एससीसी 388 757

10. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन ने कहा कि पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में निर्णय की शुद्धता का संदर्भ वर्तमान मामले के तथ्यों में सख्ती से आवश्यक नहीं हो सकता है।श्री रामचंद्रन ने 17 सितंबर 2023 को अपनी लिखित दलीलों के साथ–साथ मौखिक दलीलों के दौरान कहा कि किसी भी चुनाव लड़ने वाले दल ने पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में अनुपात को चुनौती नहीं दी है।इसके विपरीत, यह आग्रह किया जाता है कि चुनाव लड़ने वाले पक्ष अनुपात के आधार पर चुनाव लड़ें और जिस बात का विरोध करने की मांग की जाती है वह निर्णय की प्रयोज्यता है।अपीलार्थी का विचार है कि पी. वी. नरसिम्हा राव का निर्णय मामले में पूरी तरह से लागू होता है।हालाँकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि निर्णय लागू नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सदन के परिसर के बाहर आयोजित किया गया था और इसे असहमति प्रस्ताव के समान सदन की कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है।इस आधार पर, श्री रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया है कि संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी, श्री राजू रामचंद्रन से सहमत हैं कि एक संदर्भ आवश्यक नहीं है, हालांकि वे वर्तमान मामले में पी. वी. नरसिम्हा राव के फैसले के लागू होने पर असहमत हैं।श्री वेंकटरमानी के अनुसार, पी. वी. नरसिम्हा राव की शुद्धता उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव को "सदन की कार्यवाही" नहीं माना जा सकता है।श्री वेंकटरमानी मुख्य रूप से इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करते हैं:

(i) पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेम चंद्र जैन और अन्य; 5 (ii) मधुर जेतली बनाम भारत संघ और अन्य 6; और (iii) कुलदिप नायर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। 7.

12. उठाए गए मुद्दों के महत्वपूर्ण आधार के अलावा, जिसे इस आदेश के दौरान थोड़ी देर बाद संक्षेप में समझाया जाएगा, हम इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में निर्णय की शुद्धता इस मामले में उत्पन्न नहीं होती है।सबसे पहले, यह सामान्य आधार है कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय बहुमत के फैसले पर निर्भर था।

5 (1984) 2 एससीसी 404 6 (1997) 11 एससीसी 111 7 (2006) 7 एससीसी 1

पी. वी. नरसिम्हा राव। दूसरा, यह संदेह से परे है कि बचाव स्वयं बहुमत के निर्णय पर निर्भर करता है।इसलिए, वर्तमान मामले की सुनवाई के दौरान पी. वी. नरसिम्हा राव में बहुमत के फैसले में प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच की जानी चाहिए।

13. यह न्यायिक अनुशासन की एक स्थिर स्थिति है कि केवल समान शक्ति की एक पीठ ही समान शक्ति की एक पूर्व पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह करते हुए एक राय व्यक्त कर सकती है।यदि इस तरह का संदेह व्यक्त किया जाता है, तो मामले को उस पीठ के समक्ष रखा जा सकता है जिसमें उस कोरम से बड़ी कोरम हो, जिसे फैसले को चुनौती देते हुए घोषित किया गया था।8 यह निर्धारित करने के बाद कि पी. वी. नरसिम्हा राव में निर्णय की शुद्धता वर्तमान मामले में उत्पन्न होती है, हमारे लिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है कि क्या पी. वी. नरसिम्हा राव में निर्णय पर प्रथम दृष्टया पुनर्विचार आवश्यक है, और क्या मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

14. पी. वी. नरसिम्हा राव में विवाद और वर्तमान मामला, संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के प्रावधानों और संविधान के समान प्रावधान, अनुच्छेद 194 (2) की व्याख्या को बदल देता है।पहला संसद के सदनों के सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से संबंधित है, जबकि दूसरा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को समान प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

15. संविधान के अनुच्छेद 105 (2) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"105(2) संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।."

16. अनुच्छेद 105 (2) की भाषा इंगित करती है कि संसद सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में "उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में" प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।"कुछ भी कहा गया, या कोई भी वोट दिया गया" अभिव्यक्ति यह मानती है कि उन्मुक्ति आचरण के संबंध में जुड़ी हुई है, अर्थात्, एक वोट जो दिया गया है या एक भाषण जो संसद या संसद की किसी समिति में दिया गया है।अभिव्यक्ति

8 (2019) 3 एस. सी. सी. 39, पृष्ठ 79 पर अनुच्छेद 10।

"पी. वी. नरसिम्हा राव में संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए कुछ भी कहने या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में उत्पन्न हुआ। उस मामले में आरोप था कि रिश्वत लेने वालों ने सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव की हार सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत ली थी।उपरोक्त अभिव्यक्ति का विश्लेषण करते हुए, न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा ने यह विचार रखा कि अनुच्छेद 105 (2) की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि संसद सदस्यों को अदालत की कार्यवाही से बचाया जा सके जो संसद में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट से संबंधित है या संबंधित है या जिसका संबंध या संबंध है (पृष्ठ 729 पर अनुच्छेद 133)। न्यायमूर्ति भरुचा का विचार था कि कथित साजिश/रिश्वत और अनापत्ति प्रस्ताव के बीच सांठगांठ स्पष्ट थी, आरोप यह था कि कथित रिश्वत लेने वालों को संसद में अनापत्ति प्रस्ताव की हार सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत मिली थी।

17. उस मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल ने संविधान पीठ के समक्ष आग्रह किया था कि हालांकि "के संबंध में" शब्दों का व्यापक अर्थ होना चाहिए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के तहत संरक्षण उन अदालती कार्यवाही तक सीमित है जो दिए गए भाषण या दिए गए वोट या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ को बाधित करती है।यह देखते हुए कि संरक्षण का उद्देश्य संसद सदस्यों को संसद में अपने मन की बात कहने और जवाबदेह बनाए जाने के डर के बिना उसी तरह से मतदान करने में सक्षम बनाना था, न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियां शामिल हैं (अनुच्छेद 136 पृष्ठ। 730):

"... यह पर्याप्त नहीं है कि सदस्यों को दीवानी कार्रवाई और आपराधिक कार्यवाही से बचाया जाना चाहिए, जिसकी कार्रवाई का कारण उनका भाषण या उनका वोट है।सदस्यों को संसदीय बहसों में निडरता से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों को उन सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ प्रतिरक्षा की व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता होती है जो उनके भाषण या वोट के साथ संबंध रखते हैं।यही कारण है कि कोई सदस्य "अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।"अनुच्छेद 105 (2) में यह नहीं कहा गया है कि यदि विद्वान महान्यायवादी सही होते तो यह होता कि कोई सदस्य जो कुछ भी कहा है या उसने कैसे मतदान किया है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।वर्तमान अभियोजन पक्ष पर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए, किसी ऐसे सदस्य की परिकल्पना करना मुश्किल नहीं है जिसने भाषण दिया हो या ऐसा वोट डाला हो जो उन शक्तियों को पसंद न हो जो अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाते हुए परेशान की जा रही हों कि वह पक्षकार था।

संसद में एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समझौता और साजिश और उसे रिश्वत दी गई थी।."

18. विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि वह कथित रिश्वत लेने वालों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता से अवगत थे और उन्हें जो लाभ मिला है, उसके कारण उन्होंने सरकार को जीवित रहने में सक्षम बनाया।लेकिन फैसले में कहा गया, "हमारे गुस्से की भावना से हमें संविधान को संकुचित करने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए, जिससे प्रभावी संसदीय भागीदारी और बहस की गारंटी बाधित हो।" हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य नहीं है कि उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद, बहुमत का विचार था कि रिश्वत लेने वालों को शामिल करने वाली प्रतिरक्षा ने मामले में एक विशेष सांसद (श्री अजीत सिंह) की रक्षा नहीं की, क्योंकि अंततः, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में अपना वोट नहीं डाला।

19. न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल के फैसले में पी. वी. नरसिम्हा राव में दो न्यायाधीशों के विपरीत दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया था।विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि "के संबंध में" अभिव्यक्ति को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा।अल्पसंख्यकों ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 105 (2) का उद्देश्य और उद्देश्य संसद सदस्यों को स्वतंत्र रूप से बोलने या परिणामों के डर के बिना अपना वोट डालने में सक्षम बनाना है, एक ऐसी व्याख्या जो संसद सदस्यों को कानून से ऊपर रखती है, संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए प्रतिकूल होगी।इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल (दो न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए) और न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा (दो न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए) के विचारों में भिन्नता निम्नलिखित उद्धरण (पृष्ठ 673 पर पैराग्राफ 47) से सामने आती हैः

"47. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रदत्त प्रतिरक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विधायकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।संविधान में अपनाई गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली के स्वस्थ संचालन के लिए ऐसी स्वतंत्रता आवश्यक है।संसदीय लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।अनुच्छेद 105 (2) के प्रावधानों की व्याख्या जो संसद सदस्य को अपने द्वारा कही गई किसी भी बात या संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा दिए गए वोट के संबंध में रिश्वतखोरी के अपराध के लिए आपराधिक अदालत में अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा करने में सक्षम बनाएगी और इस तरह ऐसे सदस्यों को कानून से ऊपर रखेगी, न केवल संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए प्रतिकूल होगी, बल्कि कानून के शासन के लिए भी प्रतिकूल होगी जो 761 है।

यह संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा भी है।यह तय कानून है कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय अदालत को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं और मूल संरचना को मजबूत करे। (देखिएःन्यायिक जवाबदेही पर उप–समिति बनाम भारत संघ [(1991) 4 एस. सी. सी. 699] पी.719.) अनुच्छेद 105 (2) में "कुछ भी कहा गया या कोई वोट दिया गया" शब्दों से पहले "के संबंध में" अभिव्यक्ति होती है।"कुछ भी कहा गया या कोई भी वोट दिया गया" शब्दों का अर्थ केवल वह भाषण हो सकता है जो पहले ही दिया जा चुका है या एक वोट जो पहले ही दिया जा चुका है।इसलिए, दायित्व से प्रतिरक्षा केवल तभी लागू होती है जब कोई भाषण दिया गया हो या वोट दिया गया हो।ऐसे मामले में प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी जहां भाषण नहीं दिया गया है या वोट नहीं दिया गया है।जब कोई पूर्व समझौता होता है जिसके तहत संसद के किसी सदस्य को बोलने के अपने अधिकार का प्रयोग करने या सदन के समक्ष विचार के लिए आने वाले मामले पर एक विशेष तरीके से अपना वोट देने के लिए अवैध विचार प्राप्त होता है, तो दो संभावित स्थितियां हो सकती हैं।एक ऐसा समझौता हो सकता है जिसके तहत कोई सदस्य अवैध रूप से अनुदान स्वीकार करता है और संसद में नहीं बोलने या संसद में अपना वोट नहीं देने के लिए सहमत होता है।अनुच्छेद 105 (2) के तहत दी गई प्रतिरक्षा ऐसे सदस्य के लिए उपलब्ध नहीं होगी और वह आपराधिक अदालत में रिश्वत के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा।स्थिति क्या होगी यदि समझौता यह है कि भुगतान किए गए या वादा किए गए अवैध अनुग्रह के बदले में सदस्य संसद में एक विशेष तरीके से अपना वोट देगा या देगा और

वह इस तरह से बोलता है और अपना वोट देता है? श्री राव द्वारा "के संबंध में" अभिव्यक्ति के लिए सुझाए गए व्यापक अर्थ के अनुसार, अभियोजन के लिए उन्मुक्ति उस सदस्य के लिए उपलब्ध होगी जिसे बोलने या अपना वोट देने के लिए इस तरह के समझौते के तहत अवैध रूप से अनुग्रह प्राप्त हुआ है और जिसने उक्त समझौते के अनुसार संसद में बात की है या अपना वोट दिया है क्योंकि अवैध रूप से अनुग्रह की इस तरह की स्वीकृति का उस सदस्य द्वारा इस तरह के बोलने या वोट देने के साथ संबंध या संबंध है।यदि श्री राव द्वारा "के संबंध में" अभिव्यक्ति पर रखे गए निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक सदस्य पर रिश्वत के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वह सदन के समक्ष विचाराधीन मामले पर नहीं बोलने या अपना वोट नहीं देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है, लेकिन अगर वह संसद में एक विशेष तरीके से बोलने या अपना वोट देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है तो उसे इस तरह के आरोप के लिए मुकदमा चलाने से छूट मिलेगी।

और वह संसद में इस तरह से बोलता है या अपना वोट देता है।यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान निर्माताओं का इरादा संसद सदस्य के बीच प्रतिरक्षा प्रदान करने के मामले में ऐसा अंतर करना है जो संसद में एक विशेष तरीके से बोलने या अपना वोट देने के लिए रिश्वत प्राप्त करता है और बोलता है या उस तरीके से अपना वोट देता है और एक संसद सदस्य जो सदन के समक्ष आने वाले किसी विशेष मामले पर अपना वोट नहीं देने या न देने के लिए रिश्वत प्राप्त करता है और समझौते के अनुसार अपना वोट नहीं देता है या नहीं देता है ताकि पूर्व को रिश्वत के आरोप में अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की जा सके, लेकिन बाद वाले को ऐसी प्रतिरक्षा से वंचित किया जा सके।ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति से बचा जा सकता है यदि अनुच्छेद 105 (2) में "के संबंध में" शब्दों का अर्थ "से उत्पन्न" किया जाता है।यदि "के संबंध में" अभिव्यक्ति का इस प्रकार अर्थ लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रदत्त प्रतिरक्षा को उस दायित्व के लिए सीमित किया जाएगा जो संसद में किसी सदस्य या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए वोट से उत्पन्न होता है या जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।प्रतिरक्षा केवल तभी उपलब्ध होगी जब जो भाषण दिया गया है या जो वोट दिया गया है वह दायित्व को जन्म देने वाली कार्यवाही के लिए कार्रवाई के कारण का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है।संसद में किसी सदस्य द्वारा भाषण देने या वोट देने से पहले किसी कार्य के लिए दायित्व के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी, भले ही इसका संबंध सदस्य द्वारा दिए गए भाषण या वोट से हो, यदि ऐसा कार्य एक दायित्व को जन्म देता है जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है और सदस्य द्वारा संसद में भाषण देने या वोट देने पर निर्भर नहीं करता है।इस तरह के स्वतंत्र दायित्व को संसद में सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट के संबंध में दायित्व नहीं माना जा सकता है।अनुच्छेद 105 (2) के तहत जिस दायित्व के लिए प्रतिरक्षा का दावा किया जा सकता है, वह दायित्व है जो संसद में दिए गए भाषण या वोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।."

20. विशेष रूप से, न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने फैसले के दौरान इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया कि रिश्वतखोरी का मामला कब पूरा होगा।विद्वान न्यायाधीश के विचार के अनुसार, रिश्वत लेने वाले के खिलाफ रिश्वत का अपराध पूर्ण होता है, यदि वह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए पैसे लेता है या लेने के लिए सहमत होता है।धन की स्वीकृति के साथ या धन को स्वीकार करने के समझौते पर समापन पूरा होगा और यह 763 है।

प्राप्तकर्ता द्वारा अवैध वादे के निष्पादन पर निर्भर नहीं।धन प्राप्त करने वाले को सौदा करने के लिए प्रतिबद्ध माना जाएगा, भले ही वह सौदे के प्रदर्शन में चूक करता हो।इसलिए, यह न्यायमूर्ति अग्रवाल का विचार था कि रिश्वतखोरी को साबित करने के लिए, केवल यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि रिश्वत देने वाले को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए धन प्राप्त हुआ था या प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ था और आगे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसने वास्तव में वादे के अनुसार काम किया था।

21. इस मामले में तीसरा फैसला न्यायमूर्ति जी. एन. रे ने दिया। न्यायमूर्ति जी. एन. रे के फैसले को पढ़ने से संकेत मिलता है कि विद्वान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि

(i) संसद सदस्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 (सी) के तहत एक लोक सेवक है; और

(ii) चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) के तहत संसद सदस्य के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के लिए कोई सक्षम प्राधिकारी नहीं है, इसलिए न्यायालय प्रावधान में उल्लिखित कारणों का संज्ञान ले सकता है, लेकिन अभियोजन एजेंसी को आपराधिक अदालत में संसद सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने से पहले राज्यसभा के अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए।

22. उपरोक्त दो मुद्दों पर न्यायमूर्ति जी. एन. रे ने न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल के फैसले से सहमति व्यक्त की।हालाँकि, अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या पर, न्यायमूर्ति जी. एन. रे ने दो न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा के फैसले से सहमति व्यक्त की।इसलिए, अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या पर न्यायमूर्ति एस. पी. भरुचा का निर्णय तीन विद्वान न्यायाधीशों के बहुमत के विचार का प्रतिनिधित्व करता है।

23. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि श्री राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ वकील और श्री आर वेंकटरमानी, भारत के अटॉर्नी जनरल के अलावा, हमने श्री पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ वकील, जिन्हें अदालत की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है, श्री गोपाल शंकरनारायणम, वरिष्ठ वकील, जो मध्यस्थ की ओर से पेश हुए और डॉ. विवेक शर्मा, जो मध्यस्थ की ओर से पेश हुए, को भी सुना है।

24. हम न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायण के इस कथन से सहमत हैं कि

पी. वी. नरसिम्हा राव में बहुमत के निर्णय में व्यक्त किए गए निर्णय पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।ऐसा करने के लिए प्रथम दृष्टया हमारे कारण नीचे दिए गए हैं:

(i) संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के 105 (2) ए. सी. एल. ए. और ए. सी. एल. ए. एन. डी. एच. ई. के संबंधित प्रावधानों को पाठ, संदर्भ और प्रावधान के अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।संविधान के अनुच्छेद 105 (2) में अंतर्निहित मौलिक उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि संसद के सदस्य, या राज्य विधानमंडलों के सदस्य, परिणाम के डर के बिना, सदन के पटल पर या सदन में या सदन की समितियों के सदस्यों के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए।जबकि संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देता है, अनुच्छेद 105 (2) विधानमंडल के सदस्यों के महत्व को मान्यता देकर उस अधिकार को संस्थागत बनाता है, जिन्हें खुद को व्यक्त करने और प्रतिशोध या परिणाम के डर के बिना अपना वोट डालने की स्वतंत्रता है।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 105 (2) या अनुच्छेद 194 (2) का उद्देश्य प्रथम दृष्टया आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से प्रतिरक्षा प्रदान करना प्रतीत नहीं होता है जो संसद सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के रूप में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है; (ii) दूसरा, पी. वी. नरसिम्हा राव में निर्णय के दौरान, न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल ने एक गंभीर विसंगति का उल्लेख किया यदि रिश्वत लेने वाले के लिए अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रतिरक्षा के समर्थन में निर्माण को स्वीकार किया जाना था:यदि सदस्य संसद में एक विशेष तरीके से बोलने या अपना वोट देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है और वास्तव में संसद में उस तरीके से बोलता है या वोट देता है, तो किसी सदस्य को इस तरह के आरोप के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी।दूसरी ओर, कोई प्रतिरक्षा संलग्न नहीं होगी, और विधायिका के सदस्य पर रिश्वत के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा, यदि वे नहीं बोलने या 765 नहीं देने के लिए रिश्वत स्वीकार करते हैं।

सदन के समक्ष विचाराधीन मामले पर उनका मतदान होता है लेकिन वे इसके विपरीत कार्य करते हैं।न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि इस विसंगति से बचा जा सकता है यदि अनुच्छेद 105 (2) में "के संबंध में" शब्दों का अर्थ "उत्पन्न होने वाला" माना जाता है।दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में, प्रतिरक्षा केवल तभी उपलब्ध होगी जब जो भाषण दिया गया है या जो वोट दिया गया है वह कानून को जन्म देने वाली कार्यवाही के लिए कार्रवाई के कारण के लिए एक आवश्यक और अभिन्न अंग है; और

(iii) तीसरा, न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल के फैसले में विशेष रूप से इस सवाल पर ध्यान दिया गया है कि रिश्वतखोरी का अपराध कब पूरा होगा।निर्णय में कहा गया है कि अपराध धन की स्वीकृति या धन को स्वीकार करने के समझौते पर पूरा होता है और प्राप्तकर्ता द्वारा अवैध वादे के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होता है।रिश्वत लेने वाले को अपराध करने वाला माना जाएगा, भले ही वह निविदा और रिश्वत की स्वीकृति के तहत सौदेबाजी करने में विफल रहे।रिश्वत के अपराध के घटक तत्वों से संबंधित इस पहलू का विस्तार न्यायमूर्ति अग्रवाल के फैसले में मिलता है, लेकिन बहुमत के फैसले में इस पर विचार नहीं किया गया है।

25. हम ऊपर पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में फैसले की समीक्षा की मांग करने और बाद में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही करने के प्रयास सफल नहीं हुए।हम में से एक (न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़), एक के लिए समवर्ती राय देते हुए

कल्पना मेहता बनाम भारत संघ मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ 9 (पैरा 221)

यह देखने का अवसर था कि यदि पी. वी. नरसिम्हा राव के विचार की शुद्धता किसी उपयुक्त मामले में पुनर्विचार के लिए आती है, तो एक बड़ी पीठ को इस मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता है।बहुमत के दृष्टिकोण का राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के संरक्षण के लिए गंभीर प्रभाव पड़ता है।

26. उपरोक्त कारणों से, इस स्तर पर प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि बहुमत के विचार की शुद्धता

9 (2018) 7 एससीसी 1

पी. वी. नरसिम्हा राव पर सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

27. हम तदनुसार रजिस्ट्री से सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखने का अनुरोध करते हैं।

माननीय सीजेआई के समक्ष रखे जाने वाले कागजात

सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के गठन के लिए।